सामाजिक समावेशन की दिशा में डिजिटल इंडिया की भूमिका: कमजोर वर्गों की डिजिटल क्षमता और सहभागिता का अध्ययन"

कुमारी प्रीति, मनीषा[1], डॉ ममता उपाध्याय[2],

शोधकर्ता[1], प्रोफेसर[2],

कुमारी मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

संबद्ध, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

शोध सारांश:

डिजिटल भारत मिशन भारत सरकार द्वारा जुलाई 2015 में प्रारम्भ की गई एक महत्वपूर्ण योजना हैं जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त एवं साक्षर करना है। इस मिशन के अंतर्गत लागू विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभान्वित करते हुए समावेशी विकास को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य डिजिटल भारत मिशन की विभिन्न पहलों का विश्लेषण करते हुए समाज के विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक वर्गों तक इसकी पहुँच का विश्लेषण करना है तथा समावेशी विकास में बाधक कारकों की पहचान करना है। शोध पत्र में डिजिटल समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण वर्गों की डिजिटल सहभागिता तथा महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा यह रेखांकित करने का प्रयास किया गया है कि बढ़ते डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) ने वंचित वर्गों को कितना और किन रूपों में लाभान्वित किया है।

मुख्य शब्द :

डिजिटल इंडिया, वंचित वर्ग , डिजिटल समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशी विकास

परिचय :

भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है जहाँ विभिन्न जातियों आयु वर्गों तथा विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। साथ ही विभिन्न तरह की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक विषमताएँ पाई जाती हैं। ऐसे में इन विषमताओं को दूर करने तथा देश के समग्र विकास हेतु यह आवश्यक है कि सभी वर्गों को समान रुप से विकास की परिस्थितियाँ उपलब्ध हो सकें। महात्मा

गाँधी तथा आचार्य विनोबा भावे के चिंतन से उत्पन्न शब्द "सर्वोदय" हमे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान एवं समान विकास का हकदार दर्शाता है। इसका उद्देश्य समाज में अंतिम व्यक्ति तक विकास की परिस्थितियों को पहुँचाना है। यघपि विकास एक बहुआयामी अवधारणा है ,किन्तु वर्तमान समय तकनीकी उन्नति का समय है जहाँ विकास का अर्थ डिजिटल क्रांति तथा प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2015 में डिजिटल भारत मिशन का प्रारंभ किया गया था तथा वर्तमान मे इसे 10 वर्ष हो चुके हैं। यह एक ऐसा मिशन है जो तकनीक को जन-जन तक पहुँचा कर नागरिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रेरित हैं। इस मिशन का उद्देश्य केवल सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं हैं ,बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन तथा रोजगार जैसे क्षेत्रों में भी सुधार लाना है। डिजिटल इंडिया तथा सर्वोदय दोनों विचार अलग- अलग होने पर भी इनका उद्देश्य लगभग समान ही है -"जन-जन तक सुविधा, अवसर एवं विकास को पहुँचाना"। यदि 'डिजिटल इंडिया' के उद्देश्य को सही ढंग से लागू किया जाए तो वंचित वर्गों तक इसके लाभ को पहुँचा कर विकसित भारत के सपने को भी हासिल किया जा सकता हैं। इस शोध पत्र के अंतर्गत यह विश्लेषण किया गया हैं कि किस प्रकार डिजिटल इंडिया मिशन की विभिन्न पहलों के माध्यम से समाज के उपेक्षित वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है **।**

शोध पद्दति

यह शोध वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है जिसमें द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है जिनके संग्रहण का माध्यम सरकारी वेबसाइट**,** रिपोर्ट, जर्नल्स, पत्र पत्रिकाएँ एवं अन्य प्रामाणिक दस्तावेज़ हैं।

शोध अंतर (Research Gap) :

डिजिटल अवसंरचना के विकास तथा सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता ने नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है। इस विषय पर अनेक शोध किए गए है, जिनमें मुख्य रूप से डिजिटल अवसंरचना, ई-गवर्नेंस सेवाओं और सरकारी नीतियों के विश्लेषण पर ध्यान दिया गया है। हालाँकि उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ग्रामीण महिलाएँ तथा बुजुर्गों की डिजिटल क्षमता और उनकी वास्तविक डिजिटल सेवाओं में सहभागिता पर विस्तृत एवं समग्र अध्ययन अपेक्षाकृत कम है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह शोध कमजोर वर्गों की डिजिटल क्षमता तथा उनकी डिजिटल सहभागिता का अध्ययन करते हुए सामाजिक समावेशन की दिशा में डिजिटल इंडिया की वास्तविक भूमिका का विश्लेषण करने का प्रयास करता है, जिससे वर्तमान शोध-साहित्य में विद्यमान इस अंतर को आंशिक रूप से भरने का प्रयास किया जा सके।

शोध औचित्य :

यह शोध 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में डिजिटल योजनाओं की भूमिका की समीक्षा करते हुए सभी वर्गों के उदय में इसके योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। प्रस्तुत शोध हमे समावेशी विकास की अवधारणा को जानने में मदद करेगा साथ ही यह डिजिटल इंडिया पहल की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण करेगा। प्रस्तुत शोध-पत्र में उन तरीकों की खोज करने का प्रयास किया गया है जिनसे तकनीकी नवाचारों एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर समाज के सभी वर्गों के उदय एवं विकास हेतु सरकारी योजनाओं का संचालन किया जा सकता है।

सामाजिक समावेशन की अवधारणा :

सामाजिक समावेशन से तात्पर्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक जीवन में समान रूप से शामिल करना है। महात्मा गाँधी ने ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ सभी का समान रुप से विकास हो तथा सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सर्वागीण विकास के अवसर प्राप्त हो सके। महात्मा गाँधी का सर्वोदय का यह सिद्धांत राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन की पुस्तक "अंटू दिस लास्ट" से प्रेरित था। सर्वोदय की यह संकल्पना स्थिर नहीं है बल्कि समय के साथ इसके स्वरूप व माध्यम में परिवर्तन आता रहा है। वर्तमान में सर्वोदय का अर्थ समाज के प्रत्येक वर्ग- ग्रामवासियो, महिलाओं, गरीबों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेन्डर समुदायों तथा दिव्यांग जन को मुख्यधारा से जोड़ना हैं। वर्तमान समय में सामाजिक समावेशन का सिद्धांत हमे भारत सरकार की नीतियों में "सबका साथ,सबका विकास, सबका विश्वास" के रूप में दिखाई देता है, जिसमे सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुँचाना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को अवसर, संसाधन, सेवाएँ, अधिकार और सम्मान समान रूप से प्राप्त हों, चाहे उसकी जाति, लिंग, आय, शिक्षा, क्षेत्र, धर्म, शारीरिक क्षमता या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। डिजिटल सशक्तिकरण तथा सरकार द्वारा प्रेरित विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाएँ सामाजिक समावेशिता की ओर भारत के बढ़ते कदम को दिखाती हैं।

डिजिटल इंडिया पहल :

वर्तमान युग डिजिटल एवं एआई का है तथा हमारी लगभग सभी गतिविधियां इससे प्रभावित होती हैं। भारत में डिजिटल इंडिया मिशन का प्रारंभ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को किया गया जिसका उद्देश्य देश के हर कोने और प्रत्येक नागरिक के पास तक डिजिटल सुविधाओं को पहुँचाना हैं। डिजिटल इंडिया की मूल रूप से तीन संकल्पनाएं हैं। जिसमें सबसे पहले प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर/ अवसंरचना एक उपयोगी सुविधा के रूप मे प्रदान करना हैं जिसके अंतर्गत भारत के छोटे -छोटे गांव तथा कस्बे को हाई स्पीड इन्टरनेट तथा ब्रॉडबैंड सेवा के माध्यम से जोड़ना है। डिजिटल इंडिया की दूसरी मूल संकल्पना मांग आधारित शासन और सेवाएं प्रदान करना हैं जिसमें मोबाइल ऐप्लिकेशन

के माध्यम से कम से कम समय में सेवाओं को प्रदान करना हैं। नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर करना इस कार्यक्रम की तीसरी संकल्पना है। भारतीय नागरिकों डिजिटल रूप से सशक्त बनाना बेहद जरूरी हैं। इसके अन्तर्गत डिजिटल संसाधनो को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना सम्मिलित हैं।

इसके सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इसके मुख्य 9 स्तंभों की पहचान की गयी-

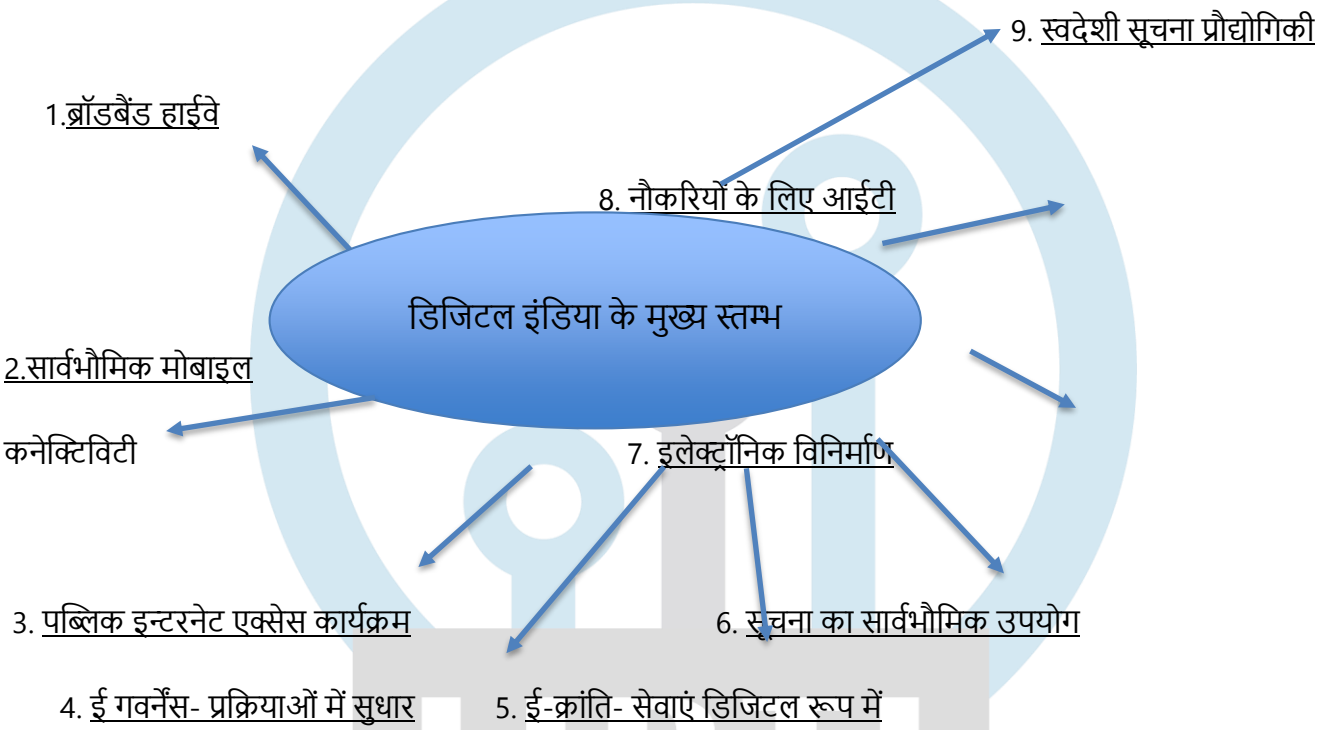

डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सामाजिक समावेशन की दिशा में की गई पहल :

डिजिटल इंडिया पहल समावेशी विकास की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है जिसमें विभिन्न छोटी-छोटी योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों एवं इलाकों तक सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास किया गया है। यह मिशन शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन तथा वित्तीय विकास को बढ़ाने तथा सभी लोगों तक समान रुप से पहुँचाने हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। इस मिशन के अंतर्गत विभिन्न सरकारी सेवाओ को उमंग एप्प के माध्यम से एकीकृत रूप से एक ही मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। उमंग एप्प एक व्यापक मोबाइल ऐप्लिकेशन है जो विभिन्न सरकारी व राज्य सेवाओं के लिए एकल मंच प्रदान करता हैं। यह एप्प हिन्दी, अंग्रेजी सहित कुल 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, PAN, EPFO, NPS, पासपोर्ट, बिल भुगतान, आयुष्मान सहित गैस सिलेंडर बुकिंग जैसी अनेक सेवाएं इस एप्प के माध्यम से एकीकृत रूप से उपलब्ध हैं। दूसरी ओर जन सेवा केंद्र भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में नागरिकों को डिजिटल और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस मिशन के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तकनीकी रूप से सशक्त, पारदर्शी,

तीव्र और उत्तरदायी बनाया गया है। डिजिटल भारत मिशन के माध्यम से शासन प्रणाली में गुणात्मक सुधार देखने को मिला है। सेवाओं की पारदर्शिता, शीघ्रता, जवाबदेही तथा नागरिक सहभागिता में वृद्धि हुई है।

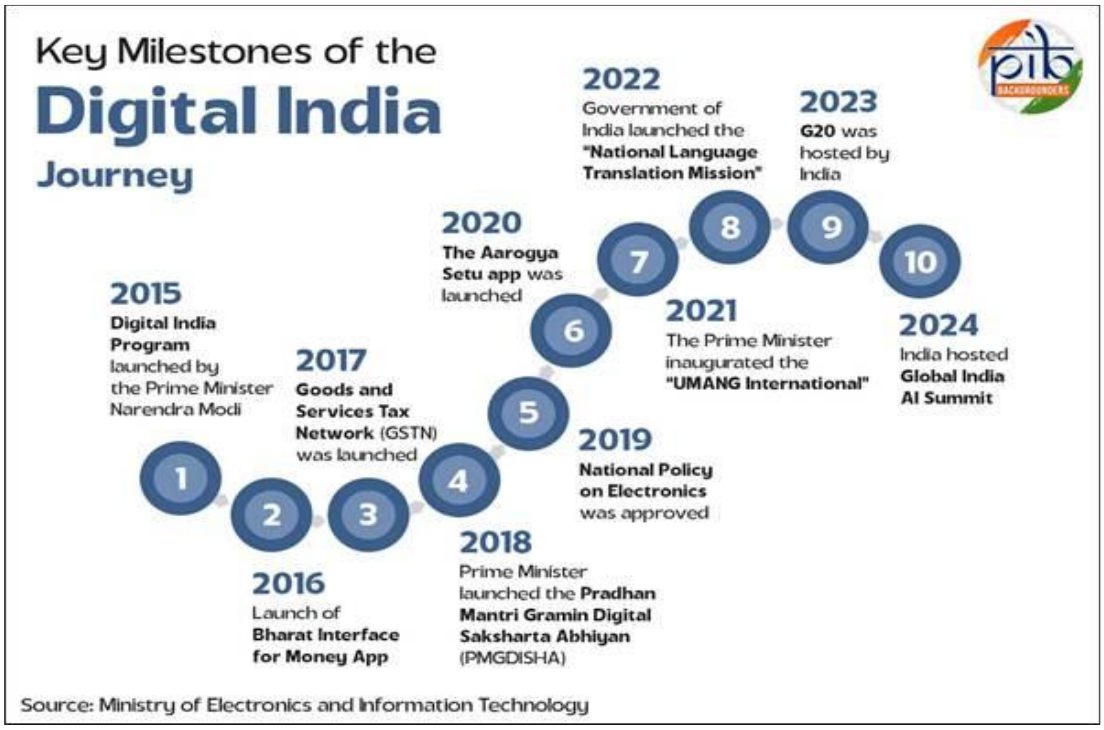

शिक्षा संबंधी पहल:

समावेशी विकास तभी संभव है जब देश के सभी वर्गों, जातियों एवं समुदायों का विकास हो और इसके लिए आवश्यक है कि सभी लोगों तक शिक्षा की पहुँच सुलभ हो सके। शिक्षा का डिजिटल प्लेटफॉर्म इसे सम्भव बनाता है जो विभिन्न प्रकार के एप्स तथा वेबसाइट्स के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराता है। सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उन्नतिशील तकनीकों को अपनाने का प्रयास किया गया है तथा कुछ नई योजनाओं एवं पहलों जैसे SWAYAM, DIKSHA, E-PATHSHALA, NDLI, NPTEL तथा PMGDISHA इत्यादि डिजिटल शिक्षा की दिशा में ही कार्यरत हैं। DIKSHA पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री सुलभ कराने का प्रयास किया जाता है। SWAYAM प्लेटफॉर्म पर स्कूल स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक विभिन्न कोर्स उपलब्ध हैं जिनमें तकनीकी, वाणिज्य, विज्ञान, कानून, प्रबंधन, स्वास्थ्य तथा कृषि जैसे विषय शामिल हैं। SWAYAM पर उपलब्ध विभिन्न पाठ्यक्रमों को UGC तथा एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है। छात्र किसी भी कोर्स की परीक्षा देकर सरकारी मान्यता प्राप्त प्रमाण- पत्र पा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में इन्टरनेट कनेक्शन कमज़ोर हैं वहाँ शिक्षा की सुविधा पहुँचाने हेतु 2017 में SwayamPrabha को सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। यह डिजिटल शिक्षा बढ़ाने का एक माध्यम हैं जिसमें टेलीविजन की सहायता से प्रत्येक दिन 24 घंटे शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रसारण किया

जाता हैं। इसमें कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक तथा तकनीकी, विज्ञान, वाणिज्य से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसमें करीब 40 चैनल उपलब्ध हैं जो अलग विषयों पर केंद्रित है तथा D2H के माध्यम से इनका प्रसारण किया जाता है।

स्वास्थ्य सेवाओं की पहल:

देश की बढ़ती आबादी के साथ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी निरंतर बढ़ रहीं हैं, ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास महत्वपूर्ण हो गया है। भारत में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में शहरों व गांवों के मध्य एक बड़ा अन्तर देखने को मिलता हैं। जहाँ एक ओर शहरों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं, वहीं दूसरी ओर गाँव में इनका अभाव देखने को मिलता है। सरकार द्वारा अपने विकास के विज़न को पूरा करने तथा जन-जन तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने हेतु विभिन्न स्तर पर प्रयास किए गए हैं। 2021 में प्रारंभ किया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में एक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करता है। इसके अंतर्गत 14 अंकों की एक यूनिक आई डी (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट या आभा आई डी) नागरिकों के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक गरीब, कमज़ोर व वंचित परिवारों को गंभीर बीमारियों से इलाज हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है ।इस योजना का लाभ पूरे देश में सभी वंचित समूहों को प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। यह भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसने करोड़ों गरीब समुदायों को जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराई हैं। इसके अलावा ORS (online registration system) सरकार द्वारा स्थापित एक पोर्टल है जिसके माध्यम से अस्पतालों में ऑनलाइन पंजीकरण तथा डॉक्टर से संबंधित अन्य जानकारी पायी जा सकती हैं। कुछ शहरों एवं रेलवे स्टेशनों पर हेल्थ ATM की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है जहां स्वास्थ्य संबंधी जांच एवं डॉक्टर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कम शुल्क पर त्वरित परामर्श प्राप्त किया जा सकता है ।

सामाजिक समावेशन की दिशा में डिजिटल इंडिया:

डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न सुविधाओं को जन तक पहुँचाना आसान हो गया हैं साथ ही शिक्षा, बैंकिंग सेवाओं, रोज़गार, सरकारी सेवाओं तथा स्वास्थ्य तक ऑनलाइन पहुँच बढ़ाकर एक समावेशी विकास सम्भव हो पाया है। ई- गवर्नेंस तथा बढ़ते डिजिटल प्रयोग से शासन में पारदर्शिता बढ़ी हैं। बढ़ती डिजिटल पहुँच ने ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़े इलाकों, महिलाओ, तथा कमजोर वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया है। कमजोर वर्गों के इस सामाजिक समावेशन को हम निम्न बिन्दुओ के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे-

- **सरकारी सेवाओं तक बढ़ती पहुँच**:

  डिजिटल क्रांति से पहले विभिन्न सेवाओं जैसे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, बिजली बिल, आधार सेवाएँ, बीमा और बैंकिंग सुविधाओ के लिए सरकारी दफ्तरों के निरंतर चक्कर काटने होते थे किन्तु अब सभी सेवाए मोबाईल पर ही

उपलब्ध हैं तथा डिजिटल साक्षरता के अभाव में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना होने से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन बढ़ा हैं तथा अब लोगों को विभिन्न प्रकार के सरकारी दस्तावेजों तथा अन्य कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं हैं, बल्कि इन सेंटर्स के माध्यम से वह अपने गाँव में ही सभी सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। अप्रैल 2025 तक, भारत में 5.34 लाख से ज़्यादा सीएससी कार्यरत हैं, जिनमें से 4.17 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में और 1.16 लाख शहरी क्षेत्रों में है। (CSC e-Governance Services India Limited, 2025)

- **<u>आधार आधारित डिजिटल पहचान :</u>**

सरकार द्वारा आधार कार्ड को नागरिकों की एक डिजिटल पहचान के रूप में लाया गया था जो दुनिया की सबसे बड़ी बॉयोमीट्रिक आईडी प्रणाली है। आधार को बैंकिंग, पेंशन, सब्सिडी तथा विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। समाज के कमजोर वर्गों को मजबूत करने हेतु जन धन योजना के तहत बैंकों में सभी के लिए खाता खुलवाने की सुविधा दी गयी। साथ ही उन्हें आधार आधारित सेवाएं उपलब्ध कराकर डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया गया हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अप्रैल 2025 तक आधार धारकों की संख्या 142.39 करोड़ बताई गई है तथा इसी समय पर देश की कुल जनसंख्या लगभग 146.39 करोड़ थी। प्रस्तुत तथ्य आधार की बढ़ती भूमिका को स्पष्ट करता है तथा बढ़ते सामाजिक समावेशन को दिखाता है।

- **<u>औद्योगिक विकास एवं स्वयं उद्यमिता संबंधी पहल-</u>**

व्यापार, रोजगार एवं स्वयं उघमिता बढ़ाने के प्रयास हेतु डिजिटल भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय-समय पर लागू किए गए है जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैन्ड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना डिजिटल MSME स्कीम तथा स्किल इंडिया मिशन। विभिन्न लक्ष्यों के साथ प्रारंभ किए गए इन प्रयासों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा पिछड़े वर्गों को तकनीकी कौशल एवं प्रशिक्षण प्रदान करना तथा लघु उघोगो के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। इन पहलों के माध्यम से औद्योगिक विकास को गति मिली है तथा कमजोर वर्गों के लिए नए अवसर उपलब्ध हुए है। भारत में लगभग 6.3 करोड़ से अधिक MSME (micro,small and medium enterprices) इकाईयाँ कार्यरत है, जो देश के GDP में लगभग 30% योगदान देती है। (Ministry of Micro,Small and Medium Enterprices,2025)। सरकार द्वारा स्थापित GeM(Government e-marketplace) प्लेटफॉर्म पर नवंबर 2025 तक 11.25 लाख से अधिक MSME विक्रेता पंजीकृत थे। इसमे 2 लाख से अधिक महिला स्वामित्व वाले उघम सक्रिय है। (Government e-Marketplace,2025)

- **<u>डिजिटल साक्षरता बढ़ाने की दिशा में प्रयास</u>**

प्रत्येक घर में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने तथा उन्हे कंप्युटर/ स्मार्टफोन, इंटरनेट, सरकारी सेवाओं तथा डिजिटल भुगतान का प्रयोग सिखाने हेतु सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) प्रारंभ किया गया तथा इसके माध्यम से लाखों ग्रामीणों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया। इसका लक्ष्य

करीब 6 करोड़ ग्रामीणों को साक्षर बनाने का था तथा दिसम्बर 2024 की ईकनामिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से करीब 6.39 करोड़ लोगों को इसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा प्रदान की गई है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद मार्च 2024 में इसे आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया।

- **इंटरनेट की बढ़ती पहुँच**

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच बढ़ाने के लिए 'भारतनेट' परियोजना का प्रारंभ किया गया जिसके पहले चरण के अंतर्गत करीब 1 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट की पहुँच को बढ़ाया गया जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक डिजिटल सेवाओ तथा डिजिटल भुगतान तथा डिजिटल शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओ तक ई पहुँच को बढ़ाया गया है। TRAI की रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 तक भारत में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या लगभग 100.28 करोड़ के पार रही। "इंटरनेट इन इंडिया 2024" की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट के कुल उपयोगकर्ताओं में से करीब 55% (488 मिलियन) ग्रामीण क्षेत्रों से है, जो यह दर्शाता है कि अब ग्रामीण क्षेत्र भी इंटरनेट के उपयोग में पीछे नहीं है। औसत भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ता प्रतिदिन **90** मिनट ऑनलाइन बिताता है**,** जिसमें शहरी उपयोगकर्ता 94 मिनट और ग्रामीण उपयोगकर्ता 89 मिनट ऑनलाइन रहते हैं, जिससे हमे ज्ञात होता है कि केवल इंटरनेट कननेक्टिविटी ही नहीं बढ़ी है, बल्कि इसका निरंतर उपयोग भी किया जा रहा है। IAMAI की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल इंटरनेट उपयोगकर्ता 2025 में 900 मिलियन से अधिक थे । अंततः पिछड़े एवं कमजोर वर्गों सभी तक इंटरनेट की पहुँच निरंतर बढ़ रही है।

- **Direct Benefit Transfer (DBT) का व्यापक उपयोग**

अब सरकार नागरिकों को दिए जाने विभिन्न प्रकार के लाभों जैसे सब्सिडी, पेंशन, योजनाओ का अनुदान तथा किसी प्रकार की स्कॉलरशिप इत्यादि को सीधे-सीधे लाभार्थी के खाते में भेजती है जिससे बिचौलियों / लीक / दुरुपयोग की संभावनाएँ कम होती हैं। प्रारंभ में इसे कुछ जिलों में लागू करने का प्रयास किया गया तथा इसकी व्यापक सफलता को देखते हुए 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्येक भारतीय का बैंक खाता होने के उद्देश्य से **(**PMJDY**)** प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ किया गया । साथ ही इन्हे नागरिकों के आधार पहचान से लिंक किया गया जिससे लाभार्थी की सही पहचान की जा सके। प्रारंभ में DBT कुछ ही योजनाओ तक सीमित था, परंतु अब इसका दायरा बढ़ गया है अब यह केंद्र व राज्यों की 300 से भी अधिक योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को सीधे-सीधे पहुँचाता है। अब यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम **(**MGNREGA)**,** राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) ओर भोजन सुरक्षा लाभ जैसी बड़ी संख्या में योजनाओं को कवर करता है।

- **महिला सशक्तिकरण का प्रयास**

महिलाओ के सामाजिक समावेशन एवं शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, वित्तीय प्रबंधन और सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नई संभावनाएँ पैदा करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म ने विभिन्न प्रकार के अवसर उत्पन्न किए है। PMGDISHA जैसे कार्यक्रमों ने महिलाओ को इंटरनेट,कंप्युटर, डिजिटल लेनदेन तथा ई गवर्नेंस जैसी सेवाओ का उपयोग करना सिखाया है। Meity की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार PMGDISHA के अंतर्गत कुल प्रशिक्षित नागरिकों में 52% महिलाएँ है। IAMAI की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 35 करोड़ महिलाए इंटरनेट का प्रयोग करती है। डिजिटल रूप से सशक्त होने के बाद महिलाएँ अब ऑनलाइन बैंकिंग तथा डिजिटल मार्केटिंग में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप इंडिया, महिला ई-हाट तथा VLE **(**village level entrepreneur**)** कुछ ऐसी मुख्य पहल है जिनके माध्यम से महिलाओ को ऑनलाइन व्यापार करने तथा कम पूँजी में व्यापार शुरू करने का अवसर प्राप्त हुआ है। **CSC** की 2023-2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1 लाख से अधिक महिलाए VLE **(**village level enterprenur) के रूप में कार्यरत हैं।

- **कृषि एवं ग्रामीण विकास**

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने किसानों को अधिक कुशल एवं आधुनिक तकनीकी पर आधारित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि क्षेत्र में डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की जो AI आधारित फसल मूल्य अनुमान तथा रिमोट सेंसिग डेटाबेस के आधार पर किसानों को सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा किसान ई-मित्र जिसके माध्यम से किसानों को फसल,मौसम,बीज, दवाई इत्यादि की जानकारी मिलती है, ई-NAM के माध्यम से 1522 से भी अधिक बाजार एवं मंडी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। जून 2025 तक 1.79 करोड़ किसानों ने ई-NAM प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया है वही दूसरी तरफ PIB की जून 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार PM-KISAN के तहत 11 करोड़ से अधिक किसान परिवार अभी तक पंजीकृत है जिन्हे प्रत्येक वर्ष 6000 रुपए की धनराशि DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है।

विद्यमान चुनौतियां

डिजिटल भारत मिशन का उद्देश्य भारत के हर क्षेत्र तक इन्टरनेट सुविधा को बढ़ाकर सुशासन एवं विकसित भारत की नीव स्थापित करना है। किन्तु कुछ ऐसी समस्याएँ एवं कमियां हैं जो इस विकास की दिशा में बाधक बन रही हैं। सर्वोदय तभी संभव हैं जब समाज के सभी वर्ग समान रुप से देश की प्रगति में अपनी भागीदारी निभा सकें । इस दिशा में विद्यमान कुछ विशेष चुनौतियाँ इस प्रकार हैं-

इन्टरनेट समस्या: कुछ पिछड़े पर्वतीय इलाकों तथा जनजातीय क्षेत्रों में अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की असमान उपलब्धता है तथा 4**G** एवं 5**G** का विस्तार यहाँ अभी भी असंतुलित है। दूसरी ओर जिन इलाकों में भारतनेट परियोजना ओर ब्रॉडबैंड के तहत इंटरनेट पहुँचाने का प्रयास किया गया है वहाँ भी नेटवर्क संबंधी समस्या बनी रहती है। विभिन्न प्रकार के शोध निष्कर्षों से यह ज्ञात होता है कि इंटरनेट व डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की असमान उपलब्धता के कारण विभिन्न पिछड़े क्षेत्र अभी भी सरकारी सुविधाओ से वंचित है।

डिजिटल साक्षरता की कमी : भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी स्मार्टफोन, इंटरनेट तथा आधुनिक तकनीकों के ज्ञान से वंचित है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ, वरिष्ठ नागरिक, पिछड़ी जनजाति के लोग तथा किसान, मजदूर इसमें शामिल है। कुछ लोग डेटा चोरी होने तथा धोखाधड़ी से बचने के लिए आनलाइन प्लाटफॉर्म्स का उपयोग ही नहीं करते, हालाँकि सरकार द्वारा समय-समय पर इस दिशा में प्रयास भी किए गए है, जैसे- **PMGDISHA** जिसके माध्यम से नागरिकों को डिजिटल साक्षर बनाने का प्रयास किया गया परंतु ऐसे ही कुछ और कदम उठाने की अभी आवश्यकता है।

डिजिटल उपकरणों की असमानता : सभी लोगों तक समान रूप से डिजिटल सेवाओ की पहुँच बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि उनके पास स्मार्टफोन, कंप्युटर, स्थायी इंटरनेट तथा अन्य तकनीकी संसाधनों तक पहुँच हो किन्तु कुछ पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा महिलाओ एवं वरिष्ठ नागरिकों के पास इन तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता का अभाव है जिसके कारण वे डिजिटल सेवाओ का आनंद नहीं ले पाते और उन्हे सरकारी सेवाओ एवं अन्य कार्यों के लिए जन सेवा केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

साइबर सुरक्षा : डिजिटल उपकरणों का प्रयोग बढ़ने के साथ-साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी तथा साइबर सुरक्षा संबंधित मामले भी बढ़े है जो चिंतनीय है। NCRB 2023 के अनुसार सभी साइबर अपराधों में 65% मामले वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े रहे। यह संकेत देता है कि डिजिटल भुगतान और DBT उपयोग करने वाले कमजोर वर्ग सबसे अधिक जोखिम में हैं। IAMAI-Kantar रिपोर्ट **(**2024) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 57% लोग डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार होने के डर से ऑनलाइन भुगतान या सरकारी ऐप्स का उपयोग कम करते हैं। महिलाएँ और वरिष्ठ नागरिक साइबर धोखाधड़ी से सर्वाधिक प्रभावित पाए गए। ऐसे आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि डिजिटल समावेशन तभी सफल होगा**,** जब नागरिकों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और जागरूकता सुनिश्चित की जाए।

सुझाव

भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की एक विशेष भूमिका है तथा इसको अधिक सुदृढ़ करने हेतु यह आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गों तक इसका लाभ समान रूप से पहुँच सके। डिजिटल साक्षरता और साइबर जागरूकता का व्यापक विस्तार अनिवार्य है, ताकि ग्रामीण, महिला, बुजुर्ग तथा कमजोर वर्ग डिजिटल धोखाधड़ी से सुरक्षित रह सकें। इसके लिए स्कूल-स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए । सरकारी एप्प एवं पोर्टल को उपयोगकर्ता–अनुकूल, बहुभाषीय और सरल इंटरफेस के साथ विकसित किया जाना चाहिए। कमजोर समूहों—जैसे महिलाएँ, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन और आदिवासी समुदाय के लिए अलग "**Inclusive Cyber Safety Policy**" बनाई जानी चाहिए। साइबर सुरक्षा को लेकर मजबूत कानून बनाने की आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में **CSC** आधारित साइबर हेल्पडेस्क की स्थापना की जानी चाहिए।

निष्कर्ष :

भारत में सामाजिक समावेशन को सुदृढ़ बनाने में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरा है। डिजिटल अवसंरचना के विस्तार, ऑनलाइन सरकारी सेवाओं की उपलब्धता, मोबाइल इंटरनेट के प्रसार और डिजिटल भुगतान प्रणाली ने समाज के वंचित वर्गों, महिलाओं, ग्रामीण आबादी और कमजोर समूहों के लिए नई संभावनाएँ निर्मित की हैं किन्तु विकसित भारत के सपने को साकार करना अभी बाकी है जिसके लिए कुछ ठोस कदमों को उठाने की आवश्यकता है जिससे सभी वर्गों को साथ में लेकर विकास के पथ पर चला जा सके तथा सबका साथ ओर सबका विकास का लक्ष्य हासिल हो सके।

Reference

1. Samajik samaveshan ki avdharna (Concept Of Social Inclusion). (n.d.). (Concept Of Social Inclusion). Retrieved October 5, 2025, from https://bedhindiarticles.blogspot.com/2025/02/concept-of-social-inclusion.html
2. About Us—Digital India | Leading the transformation in India for ease of living and digital economy | MeitY, Government of India. (n.d.). Retrieved Novemberer 20, 2025, from https://www.digitalindia.gov.in/about-us/
3. FOUNDATION, O. R. (n.d.). A Decade of 'Digital India Mission': Achievements, Gaps, and the Way Forward. Orfonline.Org. Retrieved November 26, 2025, from

https://www.orfonline.org/research/a-decade-of-digital-india-mission-achievements-gaps-and-the-way-forward

4. Digital India initiative of Government has revolutionized education access in rural areas. (n.d.). Retrieved November 26, 2025, from https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1945057
5. IAMAI & Kantar. (2024). Internet in India 2024: Internet Users in India – Setting the Context [PDF report]. IAMAI. https://www.iamai.in/sites/default/files/research/Kantar_%20IAMAI%20report_2024_.pdf
6. ETGovernment. (2024, December 5). 6.39 crore people in rural India trained in digital literacy: Centre. The Economic Times. Retrieved from https://government.economictimes.indiatimes.com/news/digital-india/6-39-crore-people-in-rural-india-trained-in-digital-literacy-centre/115996684
7. Digital India Corporation. (2024). Annual report 2023–24. Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. https://dicmedia.digitalindiacorporation.in/Copy-of-Annual-Report_2023_24
8. Pratap singh dr Arun**.** **(**2025).gramin kshetro me digital India karykrm ka prabhav. Anubodhan, 1(3), 86–104.
9. Press Release on Annual Report of TRAI for the year 2023—2024 | Telecom Regulatory Authority of India | Government of India. (n.d.). Retrieved November 21, 2025, from https://trai.gov.in/notifications/press-release/press-release-annual-report-trai-year-2023-2024
10. CSC e-Governance Services India Limited. (2025). Common Services Centres performance dashboard, April 2025. https://csc.gov.in/
11. Rural India extends lead in internet usage: IAMAI-Kantar. (2025, January 17). FE Tech Bytes. https://www.financialexpress.com/life/technology-rural-india-extends-lead-in-internet-usage-iamai-kantar-3717422/
12. Umesh, R., & Nagaraju, Y. (2025). Direct Benefit Transfer in India: Progress, challenges, and the path forward. International Journal for Multidisciplinary Research, 7(1).

13. Global Agriculture. (2025, August 13). Over 1.79 Crore farmers registered on e-NAM portal across India. Global Agriculture. https://www.global-agriculture.com/india-region/over-1-79-crore-farmers-registered-on-e-nam-portal-across-india/

14. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. (2023, June 14). PM-KISAN: Empowering annadatas by providing accessible & timely financial assistance (Fact sheet). Press Information Bureau. https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2023/jun/doc2023614212001.pdf

15. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. (2024). Annual report 2023–24. Government of India. https://msme.gov.in

16. Government e-Marketplace (GeM). (2025). GeM portal statistics and procurement data. Government of India. https://gem.gov.in